## सर्वोत्त्व न्यायालय के न्यायाधीश ने रखी प्रदेश के पहले एडीआर सेंटर की आधारशिला पहला खोनीपत में खुलेगा प्रदेश का पहला एडीआर सेंटर

बनकर तैयार होगा पढीआर सेंटर, काननी सहायता मिलने में होगी आसानी

मधीम नावास के नावधीश तब

बगारे कि वे सेंटर 8000 नगपुर में कर्तव्य जुदें है। वर्तवर में लोगों की भनका तैयार रोगा। इस ग्रीक पर जनके कानूनी अधिकार मिलाना न्यावसूति अस्तमस कवीर ने असा कि । पुनिष्टिधा करने की दिशा में पैसलीमीत न्योक्ता अताना कार र जात । की चिक्रम के केंद्र में मुश्चेन्क जातीयों का मात्रा और में अधिक सेता प्रविकास के केंद्र में मुश्चेन्क जातीयों का मात्रा और में अधिक स्वार्थ केंद्र सोनों के लिए अपनेती कहा पता है। उन्होंने कहा कि सावित हुए हैं, उसी प्रकार करने विधियताओं तथा पैपलियत महायता एवं बबन्धी सेवाओं के क्षेत्र में वालादीयरों को अब सेवा भाव से अपर् पाने के तिन एडीआ स्टर के अपने के अवश्वकत है। इस चैरान एवं सरायानको स्रोकत होंगे। चारत के सर्वोच्च नाव्यस्य के इस दोचन करोने सार्व रोक नाव्यस्य प्राप्त के सर्वोच्च नाव्यस्य अंदारत पुरितका का विभोधन स्थित। ने बता कि बत एक दशक से हो से न्यवसूर्य आन्त्रमा कर्या ने मार्काव - प्रत्यानेने के दिश्यक वे कृत विशेष - सिर्देश के प्राण्याचे च्याच्या या नामीपारसम् के सक्ष्मार में मेणाजी, कानूनी चेकानी च करूनी - व्यवस्था मेला वे अपन

कि जोगन की सभी प्रतिमाओं के साथ अपनी जा स्वी है।



# प्रदेश में बनेंगे 18 सेंटर ये रहे मीजूद

संबंधित के बिर आज सेटर की अध्यक्तिता रहे जाना एक ऐक्टिनिक कि है। समानेत के अव

राजी 18 संसम् विक्रीतारों में गारिकार सेटर - दीवार करा और विकार का स्थ स्वतीत किए जाएंगे। एतेआर संन्दर्भ की मुख न्यापक दशक्कारी स्तर के न्याविक अधिकारियों को नियुक्त किया आरया। इंग्लेने पहिला फैरातीयत रातरिक्तों की गुणकातुम् कानुसै सहस्रमा देव भी है।



सरीय कृपम बिरात में बनाय कि प्रदेश के प्रविकार के स्टब्स स्थान स्थापनी स्थापनी व किन्द्र अधिका अपनी सेवार है रहे हैं। डिस्कों से कम भी कम 50 से ६० जुनिसर एडवेकेट है। उन्होंने वहां एसे । इंडाड एकोक्ट स्पर्क भागे कि संस्था द्वारा अर संनेतन रोड पर में मुख्या कि व रुपोला के अने कोई परिसर का निर्माण किया जा मुक्ताने अल्पन करीर का बर की है। इस कोर परिसर में सार्वात अधीवत के के तम बार के सहस्त, हा समय नहीं हुआ है उसके दिना की

गोहन। सनील गार्ग भई गार्थ मही है प्रस् सने सने मा क्षेट्र गर्थस्य होने प्रक्रीआर चेंटर में ज़ीया कात के लिएकी केल = 8200 वर्ग फुट में होगा सेंटर व्य

किंग्र असम दरसर जने की सन - निस्माना हो गई है। या सुरेश गीराना वार अग्रज समाज नेटवर्क

विता व रहेती प्रकार में वी है महत्त्वा क्या है अपने के प्रकार के



स्थान के प्राप्त के प

# पृथला में लगा कानूनी जागरूकता शिविर

पलवल जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष राकेश कमार यादव अवस्था करिया के किया करिया के अपने अवस्था करिया कर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैनल के अधिवक्ता ने ग्रामीणी को कानून संबंधी जानकारी दी। 5 जनवरी को गांव गैलपुर, 6 को गांव धतीर, 7 को गांव सुजवाड़ी, 9 को गांव अगवानपर, 10 को गांत्र अकबरपर

कानून की जानका सूचना के अधिकार का उठाएं लाभ : गौड़



कि लोगों को सुचना के अधिकार के बारे में जानकारी पाप्त करने के साथ ही इसका लाभ भी उठाना चाहिए। साथ ही लोगों को मनरेगा का भी लाभ उठाना चाहिए। वे गाव जाहरी में हरियाणा विधिक सेवा पाधिकरण

द्वारा लगाए गए कानमी हरियाणा विधिक जागरूकता शिविर में बोल रहे सेवा प्राधिकरण थे। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार लोगों के लिए बहुत द्वारा आयोजित अहम है। सभी को इस कानून हुआ कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहिए। इस

नियम के तहत सभी किसी थी वेभाग की जानकारी प्राप्त कर सकते है। साथ ही न्हींने कहा कि लोगों को मनरेगा का लाभ उठाना वाहिए। इस दीरान दीपक कुमार, सन्पंच विनोद लाकड़ा, गोवधंन, अनिहा, मनोहरलाल, बरेश, उमेद



सोनीपत के जाहरी गांव में लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा के लिए जागे रूक करते अधिवत्ता संजय गींड व अर्थ कानती जेवन शायन क्यांचर

वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र से जल्द न्याय

ग्रामीणों को कानून जानकारी देती एडवोकेट माही मिलक।

आज समाज नेटवर्क

सोनीपत। गांव रसोई में मंगलवार को जागरूक किया। को हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण

उन्होंने बताया कि हमें अपने सावधानी ही इन के तत्वावधान में कानूनी सेवा अधिकारों के प्रति सचेत रहना बचाव है। इस दी 📰 मोबाइल वैन से मानवाधिकार व चाहिए। अधिकारों का हनन होने पर सिंह, जोगेन्द्र दिहर एचआईवी के विषय में लोगों को हमें कानून का सहाग लेना चाहिए। आनंद सिंह, रखुर जागरूक किया। शिविर में गांव के इस दौरान मंथन ऑर्ट ग्रुप अध्यक्ष अन्य मौजूद रहे।

सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। लीगल दीपक ने प्रामीणों द विशव है का स्थापन के वा किल्प कर का









Issue January, 2012



Patron-in-Chief Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi Chief Justice, High Court, Punjab & Haryana



Executive Chairman Hon'ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal Judge, High Court, Punjab & Haryana

Member Secretary Deepak Gupta



### HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

SCO No. 142-143, First Floor, Sector 34-A, Chandigarh - 160 022 Tel.No.: 0172-2604055, Fax No.0172-2622875, Toll Free No.1800-180-2057 Website: www.hslsa.nic.in E-mail: hslsa@hry.nic.in, hslsa.haryana@gmail.com

# LAYING OF FOUNDATION STONE OF HARYANA'S FIRST DISTRICT ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) CENTER AT SONEPAT

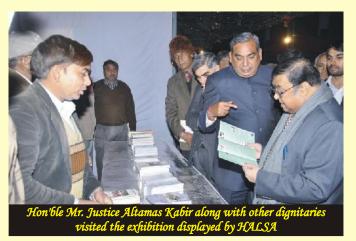
In order to improve Alternative Disputes Resolution Mechanism, Haryana State Legal Services Authority (HALSA) has decided to set up District ADR Centre in all Judicial Districts of Haryana, out of the funds provided by Thirteenth Finance Commission. For this purpose, sites have already been identified in all the districts of Haryana by A Committee appointed by Punjab &

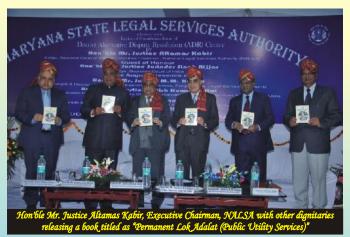


Haryana High Court. Lay out plans for District ADR Centers have been approved by the Hon'ble Building Committee of Punjab and Haryana High Court in 13 districts. A model plan of District ADR Centre, prepared by Architecture Department, Haryana, has been approved by HALSA. The PWD (B&R) Department, Haryana, has prepared standard rough cost estimate for construction of such ADR centres.

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, National Legal Services Authority laid the Foundation Stone of first District Alternative Dispute Resolution (ADR) Centre at Judicial Courts Complex, Sonipat on 24.1.2012 in the august presence of Hon'ble Mr. Justice Surinder Singh Nijjar, Judge, Supreme Court of India, Hon'ble Mr. Justice M.M. Kumar, Judge, Punjab and Haryana High Court & Executive Chairman, Punjab Legal Services Authority, Hon'ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal, Judge, Punjab and Harvana High Court & Executive Chairman, Haryana State Legal Services Authority, Hon'ble Mr. Justice Mahesh Grover, Judge, Punjab and Haryana High Court & Administrative Judge, Sessions Division, Sonipat; and Hon'ble Mr. Justice N.K. Sanghi, Judge, Punjab and Haryana High Court. Sh. Deepak Gupta, Member Secretary, Haryana State Legal Services Authority; Sh. Kuldip Jain, District and Sessions Judge-cum-Chairman, District Legal Services Authority, Sonipat; Sh. Pankaj Aggarwal, Deputy Commissioner, Sh. K.K. Rao, Senior Superintendent of Police, Judicial Officers, Members of Bar Associations, Sonipat, Gohana, Ganour, Panipat & Rohtak; Panel Advocates and Para-Legal Volunteers of District Sonipat, Panipat and Rohtak were also present at the occasion. While perusing the drawings of the Model ADR Center displayed by Architect Department, Haryana, Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir made certain suggestions. Hon'ble Mr. Justice S.K.Mittal assured his lordship to have a relook in the model plan of ADR to incorporate the suggested changes.

Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir along with other dignitaries visited the exhibition displayed by Education Department, Haryana; RUCHHI, an institution for mentally retarded children; and legal literacy books displayed by Haryana State Legal Services Authority. The dignitaries also visited Front Office of District Legal Services Authority, Sonipat and the District Mediation Center.





On this occasion, a book titled as "Permanent Lok Adalat (Public Utility Services)" was also released by Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir.

While addressing the gathering, Hon'ble Mr. Justice Kabir told that NALSA has plans to open ADR Centers in every judicial district of the country. The concept of opening these ADR centers was to have a permanent single place, where

the disputes can be resolved by any of the ADR processes like arbitration, conciliation, Lok Adalat or mediation. His lordship told that Haryana will soon get its first District Alternative Dispute Resolution Centre, which will help to provide quick settlements

out of court, which are informal in nature. His lordship also told at length about the concept of 'Legal Aid Clinics' and the scheme of Para Legal Volunteers. He said that "As Primary Health Centres have proved beneficial to the health sector, the District ADR Centre will play an important role in legal aid and legal service sector". These centres will provide the option to parties to settle their matters in satisfactory manner.



HMJ Altamas Kabir, Executive Chairman, NALSA addressing the gathering on the occasion of laying of Foundation Stone of District Alternative Dispute Resolution Center on 24.1.2012 at Sonipat

Hon'ble Mr. Justice Surinder Singh Nijjar enlightened the gathering by expressing his esteemed views. He told about the importance and necessity of legal services and legal aid, which are increasing from the last one decade.

Hon'ble Mr. Justice M.M. Kumar said that today is a historic day for Sonipat



expressing his esteemed views. He told that Haryana State Legal Services Authority will establish the District Alternative Disputes Resolution Centers in all the judicial districts of the State by the funds of 13<sup>th</sup> Finance Commission. He also disclosed that in Gurgaon, a building named as 'Tower of Justice' has been approved for 50 Courts, wherein District ADR Center in area of 20,000 sq.





because foundation stone of first ADR Centers had been laid by Hon'ble Mr. Justice Altamas Kabir in district Sonipat.

Earlier, Hon'ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal, while welcoming the dignitaries, enlightened the gathering by



ft. shall be housed on ground floor. He told that these Centers shall be run by the Judicial Officers of the level of Chief Judicial Magistrate. He also told about various activities being carried out by HALSA under the aegis of NALSA. He told that more women Para-Legal Volunteers would be involved for spreading legal awareness in the women of rural areas.

Hon'ble Mr. Justice Mahesh Grover, Judge, Punjab and Haryana High Court and Administrative Judge, Sessions Division, Sonipat thanked all the dignitaries present on this occasion.

# **MEDIATION TRAINING PROGRAMME**

Haryana State Legal Services Authority and Punjab Legal Services Authority jointly organized 40 hours Mediation Training Programme in two phases from 13<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup> January, 2012 and 20<sup>th</sup> to 22<sup>nd</sup> January, 2012 at Chandigarh Judicial Academy, Chandigarh. First phase training programme was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Satish Kumar Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court-



cum-Executive Chairman, HALSA. Hon'ble Mr. Justice Ajay Tewari, Judge, Punjab and Haryana High Court also attended the inaugural function.

While inaugurating the Session, Hon'ble Mr. Justice S.K. Mittal, Judge, Punjab and Haryana High Court-cum-Executive Chairman of Haryana State Legal Services Authority stressed that to expedite the disposal of cases, some special enactments have been brought in like the Arbitration & Conciliation Act, 1996; some amendments have been carried out in the existing laws, for instance amendments in the Legal Services Authorities Act, or the insertion of Section 89 in the Code of Civil Procedure, 1908; and some administrative measures have also been taken in this behalf. But one of the main cause for delay in disposal of the cases is the increase in the institution of cases. Though increase in the institution of case is a healthy sign of a vibrant system meant for democracy in as much as more and more people are becoming aware of legal rights of the common man and go to the Courts for enforcement of their rights or for redressal of their grievances - be it against the State, society or an individual, but at the same time we should find out ways and means for resolution of disputes as quick as possible.

His Lordship also stressed that as the alternative dispute resolution is being developed as complementary means to the judicial process, so need of time is to train judicial officers and advocates objectively on the alternative dispute resolution techniques. With this object in view, the HALSA has organized this training programme on the Art of Mediation and Conciliation.

Six Advocates Shri Joginder Pal Singh Rathee, Shri Surender Bhardwaj, Shri Sanjay Kundu, Ms.Seema Saini, Shri Tejbir Singh Deswal and Mrs. Anju Singh of District Panipat and five Advocates Shri Virender Pal Singh Sidhu, Shri Vijay Kumar Chaudhary, Shri Bhanwar Singh, Ms. Amita Kumari and Ms. Abhilasha S. Kohli of District Yamuna Nagar at Jagadhari were imparted 40 hours mediation training in two



phases by Dr. Sudhir Kumar Jain and Smt. Sangeeta Dhingra Sehgal, Members of Delhi Higher Judicial Service and Trainers of Delhi Mediation Centre deputed by Mediation and Conciliation Project Committee, Supreme Court of India.

On the concluding day of the training session, Hon'ble Mr. Justice M.M. Kumar, Judge,

Punjab and Haryana High Court & Executive Chairman, Punjab Legal Services Authority delivered the valedictory speech. His Lordship said that the concept of mediation and conciliation came from the United States of America which is a modern concept for resolving the disputes between the parties through mediation and conciliation. His Lordship pointed out that a conciliator or mediator should promote the mediation between the parties. His Lordship stressed that the mediators should have a fair knowledge of the current laws, rules and regulations and they should have capacity to resolve the dispute by mediation so that concept of mediation may be adopted properly in the society. Though, as we all know, mediation is a non-binding negotiation process and the role of the mediator is to assist the parties in the referred case to resolve dispute but knowledge of current laws would be helpful in evaluating the issues arising between the parties and in suggesting an equitable settlement.

His Lordship also pointed out that Counselling cannot achieve miracles, as it can only facilitate. It can open up the individual, give her a self-confidence, it can make her feel less lonely and believe she has someone to reach to. It is preliminary and necessary exercise that would reveal deeper issues and give a lead to other types of Counselling and remedial action or legal rights. By itself it is not complete. Its greatest contribution would be preventive-preventive of drastic action like suicide or mental breakdown; of awareness raising and education; of allowing from being taken unawares or cheated.

Certificates regarding completion of 40 hours Mediation Training Course were awarded to the Advocates by Hon'ble Mr. Justice M.M. Kumar, Judge, Punjab and Haryana High Court and Executive Chairman, Punjab State Legal Services Authority on the concluding session held on 22<sup>nd</sup> January, 2012.



# CRIMINAL MISC. PETITION NO.M-1790 OF 2012 IN ACID ATTACK ON GIRLAT ROHTAK

Haryana State Legal Services Authority through Sh. Preetinder Singh Ahluwalia, Advocate filed a criminal misc. petition u/s 482 Cr.P.C. in acid attack case on girl at Rohtak in Hon'ble Punjab and Haryana High Court and prayed that investigation of FIR No. No.283 dated 18.6.2011 under sections 326, 307, 120-B & 34 IPC be conducted in a fair and impartial manner as there have been serious lapses in the investigation conducted so far. While referring to the facts of the case, Mr. Ahluwalia submited that on 18.6.2011, certain persons attacked three girls with acid in Rohtak district. One of the victim girl later recorded her statement under section 164 Cr.P.C. and attributed the commission of crime to one Rohan. Said accused approached the High Court by way of petition under section 438 Cr.P.C. bearing CRM M-22811 of 2011 seeking pre-arrest bail. His prayer was, however, rejected on 26.8.2011. On that very day another case i.e. FIR No. 410 was registered at same police station under section 25 of the Arms Act. In said case, one accused namely Jatinder was apprehended by the police who made a disclosure statement regarding the crime committed on 18.6.2011 pertaining to acid attack. Pursuant to same, two other accused namely Naveen and Geeta Khatri were apprehended by the police. However, accused Rohan originally named by victim girl in her statement under section 164 Cr.P.C. was given a clean chit. Ld. Counsel contended further that there has been an effort by the police to exonerate Rohan by resorting to novel method of investigation. He emphasized that there are serious doubts about the manner in which investigation had been conducted. It was, however, pointed out that investigation is no longer pending as charge-sheet has been submitted pursuant to FIR No. 283 dated 18.6.2011 before the competent court of jurisdiction.

After hearing above contensions, Hon'ble Mr. Justice Rajan Gupta, Judge, Punjab and Haryana High Court issued notice of motion for 1.2.2012 to the Central Bureau of Investigation through its Superintendent of Police (Special Crime) Chandigarh on 23.1.2012. In the meantime, proceedings before the trial Court were directed to remain stayed. Now the petition is fixed for 22.2.2012.

# CONDUCTING MOBILE LOK ADALAT/LEGAL AWARENESS CAMPS THROUGH BELERO VAN.

Sh. S.K.Garg, Additional District & Sessions Judge, Palwal showing flag with Sh. Parveen Kumar, Chief Judicial Magistrate, Palwal and Legal Aid Counsels, Palwal departure of "Bolero Van" for Legal Awareness Camps on 3.1.2012.

